

राष्ट्रीय शहरी नीति

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग (1988) की रिपोर्ट और एक ही दशक में लगातार दो राष्ट्रीय आवास नीतियों के बावजूद देश में अभी भी एक राष्ट्रीय शहरी नीति तैयार की जानी है। राज्य सरकारों ने शहरी विकास, संसाधनों व संभावनाओं की तर्ज पर अपनी संबंधित राज्य शहरीकरण कार्यनीति रिपोर्ट तैयार की है। राष्ट्रीय स्तर पर, योजना आयोग ने 1995 में शहरी परिप्रेक्ष्य और नीति पर एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। शहरी परिप्रेक्ष्य और नीति, शहरी अवस्थापना और शहरी नियोजन विषय पर तीन तकनीकी समूह भी गठित किए गए। डा0 आर्कोट रामाचन्द्रन की अध्यक्षता में शहरी नियोजन प्रणाली पर तकनीकी समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। श्री वेघुल और प्रो0 वाई के अलग की अध्यक्षता में अन्य दो तकनीकी समूहों की रिपोर्ट को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है। तकनीकी समूह की अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद कार्यबल इसकी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। इससे राष्ट्रीय शहरी नीति के लिए इनपुट उपलब्ध होंगे।